शब्दबाणों का प्रहार
राष्ट्रबाण
सिवनी
संपादकः संजय बघेल
मध्य भारत का सबसे लोकप्रिय अखबार

शनिवार 26 अप्रैल 2025 • वर्ष : 10 • अंक : 42 • पृष्ठ : 08 • मूल्य : 5.00 रुपए
www.facebook.com/rashtrabaan www.twitter.com/rashtrabaan

न्यूज ब्रीफ

एम्स भुवनेश्वर ने पहली रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर ने 66 साल की महिला पर पहली रोबोटिक घुटना रिप्लेसमेंट सर्जरी की है। संस्थान ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। संस्थान ने कहा कि यह ओडिशा और पूर्वी भारत के सरकारी क्षेत्र में पहली रोबोटिक नी सर्जरी है। एम्स भुवनेश्वर के कार्यकारी निदेशक आशुतोष बिस्वास ने कहा, एम्स के ऑर्थोपेडिक्स विभाग ने 66 साल की महिला पर पहली रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की।

राहुल और सोनिया को नोटिस जारी करने से कोर्ट का इनकार

नईदिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें ईडी से दस्तावेज लाने को कहा है। जज ने कहा, 'मैं संतुष्ट होने तक ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकता।' मामले की अगली सुनवाई 2 मई, 2025 को होगी।

बंगाल के बीरभूम में विस्फोट से घर की छत उड़ी, जांच जारी

बीरभूम। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शुक्रवार सुबह एक विस्फोट हुआ, जिससे घर की छत उड़ गई और दीवार गिर गई। यह घटना सैंथिया पुलिस स्टेशन के पास सिजा गांव में हुई। विस्फोट के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, घर के मालिक ने मलबे को हटाने के लिए अर्थ मूवर लगाया था। घटना के बाद से ही मालिक घर से फरार है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, घटना में किसी की मौत या गंभीर चोट की कोई खबर नहीं है। विस्फोट का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है।

पूर्व इसरो चीफ के. कस्तूरीरंगन का 84 की उम्र में निधन

नईदिल्ली। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) के पूर्व चीफ के. कस्तूरीरंगन की शुक्रवार सुबह मौत हो गई। वह 84 साल के थे। अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु में अपने घर पर कस्तूरीरंगन ने अंतिम सांस ली। 27 अप्रैल को उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (बीएसएफ) में रखा जाएगा। कस्तूरीरंगन 1994 से 2003 तक इसरो चीफ थे। वे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे।

पहलगाम हमले के बाद पहला जुमा, नमाजियों ने काली पट्टी बांधी

हमें बॉर्डर पर छोड़ दो, साबित कर देंगे हम देश के मुस्लिम वफादार

नई दिल्ली। एजेंसी

पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आज पहले जुमे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आतंकी घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान और आतंकियों का पुतला जलाए गए। साथ ही हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के शाही इमाम मौलाना कारी सैयद फजलुल मन्नान रहमानी ने नमाज के बाद कहा- पीएम मोदी जो भी फैसला करेंगे, हम सब उनके साथ हैं और उनके हर फैसले का समर्थन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदर्शन के दौरान मुस्लिमों बोले- प्रधानमंत्री से हमारी अपील है कि पाकिस्तान बॉर्डर खोल दो और हिंदुस्तान के मुसलमान को बॉर्डर पर छोड़ दो। हम साबित कर देंगे कि देश के मुसलमान वफादार हैं। आतंकवाद किसी धर्म या देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता, आतंकियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 जनवरी को आतंकियों ने टूरिस्ट्स पर फायरिंग की थी। इसमें 1 नेपाली नागरिक समेत कुल 26 लोग की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हुए थे।

एमपी में मुस्लिमों का प्रदर्शन

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जुमे की नमाज के बाद पहलगाम आतंकी हमले का विरोध हुआ। नमाज के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इसके बाद आतंकवाद का पुतला दहन किया। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। धर्मगुरु मौलाना सय्यद अनस अली ने कुरान की आयत का जिक्र करते हुए कहा, अल्लाह ने फरमाया है कि जिसने एक इंसान को मारा, उसने पूरी इंसानियत को मारा। हमारे भारतीयों का खून बहाया गया है, यह दुख और शर्म की बात है। धर्म का नाम बदनाम किया जा रहा है। हम पाकिस्तान और आतंकवाद से बदला लेना चाहते हैं।

उमर अब्दुल्ला बोले-कभी सिंधु समझौते के पक्ष में नहीं थे

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को श्रीनगर में पहलगाम हमले में घायल लोगों और उनके परिजन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आतंकी कितनी भी कोशिश कर लें, हम उन्हें हरा देंगे। हर भारतीय एकसाथ है।

इससे पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे अपने-अपने राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें वापस भेजें।

हमले के 3 दिन बाद सेना ने बड़ा एक्शन लिया। जम्मू-कश्मीर के त्राल और अनंतनाग के बिजबेहरा में 2 लश्कर आतंकियों के यहां सर्च ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान दोनों के घरों में रखा एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो गया। धमाके में आसिफ शेख और आदिल ठोकर के घर पूरी तरह तबाह हो गए।

इधर, बांदीपोरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। 2 जवान भी घायल हैं। पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल की दोपहर आतंकवादियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की थी। हमले में 26 टूरिस्ट मारे गए थे। 10 से ज्यादा घायल हैं।

1984 दंगों के याचिकाकर्ता ने पीएम को चिट्ठी लिखी

1984 सिख विरोधी दंगों के मुख्य याचिकाकर्ता वकील गुरलाड सिंह कहलों ने पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहलों ने हमले को लेकर शोक जताया है। कहलों ने लिखा कि पहलगाम जैसी घटनाएं पुरानी यादें ताजा कर देती है। कहलों ने मोदी से अपील की है कि विभाजनकारी ताकतों पर सख्त एक्शन लिया जाए।

उमर अब्दुल्ला बोले- हम कभी सिंधु जल समझौते के पक्ष में नहीं थे

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कहा कि भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है, हम कभी भी सिंधु जल समझौते के पक्ष में नहीं रहे हैं। हमारा हमेशा से मानना रहा है कि सिंधु जल संधि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए सबसे गलत दस्तावेज है।

राहुल बोले- आतंकी कुछ भी कर लें, हम उन्हें हरा देंगे

राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहां हालात देखने आया हूं। जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों ने हमले की निंदा की है। उनका देश को पूरा समर्थन है। मैंने घायल लोगों से मुलाकात की। जिन्होंने भी अपने परिवार का सदस्य खोया है, उन सबके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। हमने कल सरकार के साथ मीटिंग की थी। पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर हमले की निंदा की। हमने कहा कि सरकार जो भी फैसला लेगी, हम उसके साथ हैं। आतंकी घटना के पीछे यही मकसद था कि समाज को तोड़ा जाए, भाई को भाई के खिलाफ लड़ाया जाए। हर भारतीय एकसाथ है।

सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित की गई

भारत ने पाकिस्तान को भेजा आधिकारिक पत्र; पाकिस्तान बोला– इसे जंग माना जाएगा

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था। गुरुवार देर रात भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी गई। भारत में जल शक्ति मंत्री सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि, यह संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता।

पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के खत्म होने को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। पाकिस्तानी सरकार ने कहा- अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग की तरह माना जाएगा। पहलगाम के नजदीक बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। इनमें एक नेपाली नागरिक शामिल था। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके बाद भारत ने जल संधि स्थगित करने सहित 5 बड़े फैसले लिए थे।

बीएसएफ जवान को कैद में रखने का मामला बढ़ा

बीएसएफ डीजी ने गृह सचिव से बात की; पाकिस्तानी रेंजर्स ने पंजाब बॉर्डर से पकड़ा था

फिरोजपुर। एजेंसी

पंजाब में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से पकड़े बीएसएफ जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने 48 घंटे बाद भी नहीं छोड़ा। जवान को छुड़ाने के लिए बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी ने इसे लेकर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से बात की है। इससे पहले बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स की मीटिंग भी बेनतीजा रही। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों में तनाव है। पाकिस्तानी रेंजर्स के रवैये को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

उधर, मीडिया से बातचीत करते हुए बीएसएफ जवान पीके साहू के भाई श्यामसुंदर साहू ने केंद्र सरकार और बीएसएफ अधिकारियों से तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि सरकार उनकी सुरक्षित और तत्काल वापसी सुनिश्चित करे। पूरा परिवार बेहद चिंतित है।

भाजपा के राजा इकबाल सिंह दिल्ली के मेयर चुने गए, कांग्रेस को सिर्फ 8 वोट मिले

आम आदमी पार्टी चुनाव में शामिल नहीं हुई

नई दिल्ली। एजेंसी

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव के लिए शुक्रवार को वोटिंग हुई। इसमें भाजपा उम्मीदवार राजा इकबाल सिंह ने जीत हासिल की। राजा को 133 वोट मिले। राजा इकबाल एमसीडी में विपक्ष के नेता थे और इससे पहले वे नॉर्थ एमसीडी के मेयर रह चुके हैं।

चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मंदीप सिंह को महज आठ वोट ही मिले। एक वोट अवैध घोषित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी (आप) ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। आप ने कहा था कि बगैर किसी बाधा के भाजपा अपना मेयर बना ले और चार इंजन की सरकार बिना बहाना बनाए चलाए।

इसके अलावा भाजपा के बेगमपुर वार्ड से पार्षद जय भगवान यादव डिप्टी मेयर चुने गए। इससे पहले वे विपक्ष के उपनेता थे। इस पद के लिए कांग्रेस ने अबुल फजल एन्क्लेव वार्ड से अरीबा खान को उतारा था। चुनाव में भाजपा की जीत पहले ही तय थी क्योंकि भाजपा के पास 117 और कांग्रेस के पास सिर्फ आठ पार्षद थे।

पहले से तय थी भाजपा की जीत भाजपा दो साल बाद एमसीडी में फिर से सत्ता हासिल की। एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव में 250 पार्षदों के अलावा दिल्ली के 10 सांसद (लोकसभा से सात और राज्यसभा से तीन) और 14 विधायक भी वोट डालते हैं।

हालांकि, इस समय 238 निगम पार्षद ही हैं। 11 पार्षदों के विधायक बनने और एक के सांसद बनने से कुल 12 सीटें खाली हुई हैं। इस लिहाज से वोट देने वालों की कुल संख्या 262 होती है। एमसीडी में इस समय भाजपा के 117, आप के 113 और कांग्रेस के 8 पार्षद हैं।

हमले से दुखी होकर छोड़ा इस्लाम, हिंदू धर्म अपनाया

इंदौर में दरगाह परिसर में कराई हनुमान चालीसा; भंडारा भी कराया

इंदौर। एजेंसी

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने इंदौर के एक मुस्लिम का हृदय परिवर्तन कर दिया। शहाबुद्दीन नाम के इस शख्स ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। उसने नाम बदलकर श्यामू रख लिया।

उसने ये भी कहा कि जिस दरगाह परिसर में वह कव्वाली का आयोजन कराता था, वहां अब केवल हनुमान चालीसा, रामायण और सुंदरकांड का पाठ होगा। श्यामू ने इस मौके पर दरगाह परिसर में ही हनुमान चालीसा पाठ और भंडारे का आयोजन भी किया। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। ये घटनाक्रम इंदौर के कुलकर्णी भट्टा इलाके का है। दरअसल, श्यामू पहले हिंदू ही था, उसने कव्वाली से प्रभावित होकर मुस्लिम धर्म अपना लिया था। अब, जब उसे पता चला कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी तो उसने दरगाह में होने वाली कव्वाली बंद कर दी।

आतंकियों का समर्थन गलती : पाक रक्षा मंत्री

अमेरिका के कहने पर 30 साल से यह गंदा काम कर रहे; सजा भुगत रहे

इस्लामाबाद। एजेंसी

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना है कि उनका देश पिछले 30 साल से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह 'गंदा काम' कर रहे हैं।

ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को ब्रिटिश अखबार द स्काई को दिए इंटरव्यू में यह बातें कहीं। ब्रिटिश एंकर यल्दा हकीम ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या पाकिस्तान आतंकी गुटों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है? इस पर उन्होंने कहा कि वैश्विक शक्तियों ने अपने हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया।

ख्वाजा आसिफ ने यह भी माना कि आतंकियों का समर्थन करना या ट्रेनिंग देना बड़ी गलती थी। हम इसकी सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा- अगर हम सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होते और और 9/11 के हमलों के बाद जो हालात बने, वो न बनते तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेदाग होता।

आसिफ बोले- दोनों देश परमाणु शक्ति, दुनिया को चिंतित होना चाहिए

पहलगाम मामले को लेकर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ विवाद दोनों देशों के बीच बड़े जंग का रूप ले सकता है। उन्होंने कहा कि भारत जो भी करेगा, पाकिस्तान उसका जवाब देगा। अगर चीजें गलत हुई तो इस टकराव का असर खतरनाक हो सकता है। पाक रक्षा मंत्री ने कहा कि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान नहीं, बल्कि भारत दोषी है। यदि भारत हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेता है, तो पाकिस्तान उसका उसी तरह जवाब देगा। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के पास जवाब देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया को चिंतित होना चाहिए क्योंकि दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं।

कहा– धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी याचिकाएं खारिज की जाएं

वक्फ कानून पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

नई दिल्ली। एजेंसी

वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र ने कहा, वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है।

केंद्र ने वक्फ (संशोधन) की वैधता के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज करने की मांग की। केंद्र ने कहा, अदालतें वैधानिक प्रावधान पर रोक नहीं लगा सकती, संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकती हैं और निर्णय दे सकती हैं। संसद में बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की धारणा लागू होती है। विधायिका द्वारा लागू की गई विधायी व्यवस्था को बदलना स्वीकार नहीं है।

केंद्र के हलफनामें में 7 बड़ी दलीलें

- अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि संशोधन से धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाएगा। आप इस बिंदु पर विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की विधायी क्षमता और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर समीक्षा कर सकता है।
- इस संशोधन कानून से किसी भी व्यक्ति के वक्फ बनाने के धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। केवल प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस कानून में बदलाव किया गया है।
- संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है, विशेष रूप से संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की सिफारिशों और संसद में व्यापक बहस के बाद बने हुए कानून को।
- संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हुए यह सुनिश्चित किया कि वक्फ जैसे धार्मिक बंदोबस्त का प्रबंधन किया जाए और उसमें जताया गया भरोसा कायम रहे।
- निजी और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने के लिए प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है।
- मुगल काल से पहले, आजादी से पहले और आजादी के बाद वक्फ की कुल जमीन 18 लाख 29 हजार 163 एकड़ थी। चौंकाने वाली बात यह है कि 2013 के बाद वक्फ भूमि में 20,92,072.536 एकड़ की वृद्धि हुई।
- वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 वैध विधायी शक्ति का वैध प्रयोग है।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को 7 दिन के अंदर केंद्र से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा था। इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

संपादकीय

पाक नहीं सुधरेगा

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, भारत सरकार सख्त कदम उठाने के मूड में है। गुरुवार को हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सरकार को आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए कहा। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने भी सड़कों पर उतरकर हमले की निंदा की।

जैसी कि उम्मीद थी, पहलगाम आतंकी हमले पर गुरुवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भारतीय राजनीति का वह रूप दिखा, जिसकी जरूरत थी। सभी दलों ने एक स्वर में सरकार से कहा कि आतंक को मुंहतोड़ और निर्णायक जवाब देने के लिए जो भी जरूरी हो, किया जाए। इससे पहले जम्मू-कश्मीर, खासकर घाटी में जिस तरह से आम लोगों ने सड़कों पर निकलकर इस आतंकवादी हमले की भर्त्सना की, वह पूरी दुनिया के लिए स्पष्ट संदेश है।

पाक की खिसियाहट: इस बीच पाकिस्तान ने शिमला समझौता समेत तमाम समझौते स्थगित करने और पानी रोकने जाने को युद्ध का ऐलान मानने जैसी घोषणाएं करके यह दिखाने की कोशिश की है कि वह भी भारत के कदमों का मुकाबला करने में सक्षम है। बेहतर होता कि हमले के पीछे जिस आतंकवादी संगठन का हाथ है, वह उसके खिलाफ कार्रवाई करता। आखिर, पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित रहा है और वह जब तब इसकी दुहाई देता आया है।

सख्त संदेश: आतंकवादी हमले की घटना के बाद केंद्र सरकार ने जिस तरह से रिएक्ट किया, उससे साफ हो गया कि देश अब ऐसे हमलों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। गुरुवार को भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन जैसे तमाम प्रमुख देशों के राजदूतों को घटना का पूरा ब्यौरा दिया और इससे जुड़े तमाम साक्ष्य उनके साथ साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फिर से यह बात दोहराई कि पुलवामा के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच वायुसेना ने रफाल और सुखोई-30 ने आक्रमण अभ्यास भी किया।

पानी रोके जाने का डर: सिंधु जल समझौते को स्थगित करने की घोषणा ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चिंतित किया है। यह बहुत बड़ी घोषणा है और इसके निहितार्थ दूर तक जाते हैं। लेकिन भारत का मकसद भी यही है कि सब इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लें कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। आखिर, दशकों से सीमापार आतंकवाद को बंद करने की भारत की अपील को पाकिस्तान अनदेखा करता आया है।

निरंतरता की जरूरत: दरअसल में, पाकिस्तान में आतंक के ढांचे को नेस्तनाबूद करने के खातिर निरंतर प्रयासों की जरूरत है। पाकिस्तान को अहसास दिलाना होगा कि आतंक को संरक्षण देने की नीति कहीं की नहीं छोड़ेगी।

भारत की ओर से आतंक के विरुद्ध उठाए गए ये कदम पाकिस्तान को नागवार गुजरेंगे, लेकिन सच यह है कि लंबे समय से भारत में आतंकवाद की समस्या को और ज्यादा जटिल बनाने में पाकिस्तान की जो भूमिका रही है...

आतंक पर आर-पार की तैयारी, सिंधु से सीमा तक सख्ती, पाकिस्तान को कड़ा संदेश

जम्मू जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले का स्वरूप ऐसा है कि भारत सरकार के लिए इस मसले पर ठोस कार्रवाई करना वक्त की जरूरत है। इसलिए भारत ने इस बर्बर घटना के बाद सख्त कदम उठाते हुए अगर पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है तो यह स्वाभाविक है। यह जगजाहिर हकीकत है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है। इसलिए भारत के सामने अब एक तरह की मजबूरी आ खड़ी हुई है कि वह आतंकवाद और उसे शह देने वाले देश के खिलाफ नीतिगत स्तर पर कोई ठोस कदम उठाए।

इसी क्रम में गुरुवार को भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध कई कड़े कदम उठाने की घोषणा की। इनमें पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा पर पाबंदी, दूतावास में राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कटौती, अटारी-वाघा सीमा को बंद करना और सबसे अहम छह दशक पुरानी सिंधु जल संधि के क्रियान्वयन को निलंबित करना शामिल है।

जाहिर है, भारत की ओर से आतंक के विरुद्ध उठाए गए ये कदम पाकिस्तान को नागवार गुजरेंगे, लेकिन सच यह है कि लंबे समय से भारत में आतंकवाद की समस्या को और ज्यादा जटिल बनाने में पाकिस्तान की जो

भूमिका रही है, उसने कई स्तर पर मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर, आतंकवाद को बढ़ावा देने में अपने भूमिका पर शर्मिंदा होने के बजाय पाकिस्तान इस मसले पर आमतौर पर अपनी हठधर्मिता ही प्रदर्शित करता रहा है। इस बार भी जब भारत ने कुछ सख्ती दिखाई तो हकीकत स्वीकार करने के बजाय पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत के साथ द्विपक्षीय शिमला समझौते को निलंबित करने, हवाई क्षेत्र और सीमाओं को बंद करने जैसे कुछ कदम उठाने की घोषणा कर दी।

सवाल है कि ऐसा करके पाकिस्तान क्या साबित करना चाहता है। पहलगाम में आतंकी हमला आतंकवादियों के अपने एजंडे के लिए क्रूरता की हर हद को पार करने की मंशा का सबूत है। वरना क्या कारण है कि कश्मीर गए जिन पर्यटकों का उद्देश्य वहां घूमना-फिरना और प्रकृति के सौंदर्य के बीच खुशी के कुछ पल गुजारना था, उन्हें भी मार डालने में आतंकियों को कोई हिचक नहीं हुई।

इस हमले का एक सीधा असर जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर चोट भी है। सवाल है कि इस तरह की क्रूरता करके आतंकवादी किसके हित में काम कर रहे हैं। समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत सबूतों के साथ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा करता रहा है। मगर पाकिस्तान हर बार इसे महज आरोप बताता है। जबकि भारतीय सीमा में घुसपैठ से लेकर आए दिन होने वाले आतंकी हमलों में पाकिस्तान के संरक्षण के तथ्य सामने आते रहे हैं।

फिलहाल पाकिस्तान जल संकट से दो-चार है और ऐसे में अगर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की है तो इससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी। पहलगाम में पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी और उसमें काफी लोगों की मौत के बाद भारत ने जो सख्त कदम उठाने की घोषणा की है, उसमें यह संदेश साफ है कि अगर पाकिस्तान आतंक के रास्ते भारत को अस्थिर करने और निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादी संगठनों को समर्थन और शह देना जारी रखता है तो उसे इसके नतीजे भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।

विकास दर की गिरावट पर विश्व बैंक की चेतावनी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और आर्थिक सहयोग विकास संगठन के बाद विश्व बैंक ने जिस तरह भारत के वृद्धि अनुमान में 0.5 फीसद तक की कटौती की है, उससे बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। मगर सवाल यह है कि जब हम भारत को अगले कुछ वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के दावे कर रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है कि वृद्धि अनुमान बार-बार डगमगाते दिखते हैं।

यह सच है अमेरिका की नई व्यापार नीति के बाद छिड़े शुल्क संग्राम के बीच दुनियाभर में अनिश्चितता का माहौल है। चीन से उसका टकराव बढ़ने से स्थितियां बिगड़ी ही हैं। वहीं पिछले एक दशक में आए कई झटकों की वजह से पूरे दक्षिण एशिया के देशों के पास मौजूदा वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए सीमित उपाय ही हैं।

इस बीच वैश्विक एजंसियों ने भारत का वृद्धि अनुमान घटा कर एक तरह से हमें सचेत किया है। हालांकि यह उम्मीद अब भी है कि देश तेजी से बढ़ रही दुनिया का प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा और वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ने पर भी भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 6.2-6.7 की दर से बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक को भी उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था इसी दर से बढ़ती रहेगी। भारत के आर्थिक विकास में गिरावट की जो वजहें बताई जा रही हैं, उनमें नीतिगत अनिश्चितता तो है ही, वहीं सार्वजनिक पूंजी निवेश भी घटा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम उम्मीद से कम विकास कर पाए हैं, तो इसे गंभीरता से लेना होगा। उद्योग, कृषि-व्यापार और कई क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के दौरान हमें यह भी देखना होगा कि विकास के क्रम में अगर आम आदमी पीछे छूट रहा है, तो इसका क्या कारण है।

चिंता की बात है कि उपभोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए करों में कटौती और कई बदलावों के बावजूद निजी निवेश की गति मंद पड़ रही है।

व्यापार

प्रोसेसिंग फीस जीरो, ब्याज पर राहत... होम लोन के लिए पीएनबी दे रहा बड़े तोहफे

पीएनबी ने ग्राहकों के लिए लोन कैंपेन की शुरुआत की है। इस कैंपेन को पीएनबी निर्माण 2025 नाम दिया गया है। आइए जानते हैं कि बैंक ने इस कैंपेन के तहत किस तरह की सुविधाएं शुरू की हैं।

पब्लिक सेक्टर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से लोन लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, पीएनबी ने ग्राहकों के लिए लोन कैंपेन की शुरुआत की है। इस कैंपेन को पीएनबी निर्माण 2025 नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य हाउसिंग और ऑटो लोन को अधिक किफायती बनाना है। इसके जरिए ग्राहकों को अट्रैक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। आइए जानते हैं कि बैंक ने इस कैंपेन के तहत किस तरह की सुविधाएं शुरू की हैं।

पीएनबी निर्माण 2025 कैंपेन की खास बातें

हाउसिंग और कार लोन पर जीरो प्रोसेसिंग और डॉक्युमेंटेशन फीस जीरो है। इसके अलावा घर के पुराने लोन को पीएनबी में ट्रांसफर करने पर कोई नॉन-एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट चार्ज नहीं लगेगा। वहीं, ग्राहकों को लोन पर 5 आधार अंकों (बीपीएस) की ब्याज दर रियायत भी दी जाएगी।

रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट में कटौती

पीएनबी ने अपनी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट को 8.90 फीसदी से घटाकर 8.65 फीसदी कर दिया है। यह नई दरें 10 अप्रैल 2025 से लागू हैं। रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट शब्द का मतलब है रेपो रेट से जुड़ी ब्याज दर। अक्टूबर 2019 में जारी आरबीआई के एक सर्कुलर में बैंकों को अपने रिटेल लोन को बाहरी बेंचमार्क लेंडिंग दरों से जोड़ने का आदेश दिया गया है, जिन्हें ई-बीएलआर के रूप में जाना जाता है। ऐसे में रेपो दर अधिकांश बैंकों के लिए बेंचमार्क बन गई है।

बैंक के लोन में ग्रोथ

पंजाब नेशनल बैंक के मुताबिक उसने मार्च तिमाही में 13.6 प्रतिशत की लोन ग्रोथ दर्ज की है। इस दौरान उसका लोन बढ़कर 11.17 लाख करोड़ रुपये हो गया है। 31 मार्च, 2024 के अंत में उसका कुल अग्रिम 9.83 लाख करोड़ रुपये था। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के अंत में बैंक की कुल जमा 13.69 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 14.3 प्रतिशत बढ़कर 15.65 लाख करोड़ रुपये हो गई है। बैंक का कुल कारोबार 31 मार्च, 2024 के अंत में 23.53 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 14 प्रतिशत बढ़कर 26.83 लाख करोड़ रुपये हो गया।

1 शेयर पर 57 का मुनाफा देगी यह कंपनी

बीएसई 200 टेक्नोलॉजी कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के लिए 57 रुपये के अंतिम डिविडेंड की घोषणा की है।

बीएसई 200 टेक्नोलॉजी कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के लिए 57 रुपये के अंतिम डिविडेंड की घोषणा की है। सॉफ्टवेयर और कंसल्टेंसी कारोबार में लगी सक्रिय कंपनी ने 24 अप्रैल को तिमाही और वित्त वर्ष के नतीजे घोषित किए और डिविडेंड का ऐलान भी किया। हम बता कर रहे हैं- एमफैसिस लिमिटेड (Mphasis Ltd) की। एमफैसिस लिमिटेड के शेयर आज 3प्रतिशत तक चढ़कर 2525.40 रुपये पर बंद हुए।

क्या है डिटेल

बोर्ड मेंबर्स ने 24 अप्रैल, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 57 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम डिविडेंड प्रस्तावित किया था, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अप्रूवल के तहत है और यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप लगभग 10,835.46 मिलियन रुपये का नकद बहिर्वाह होगा। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, ÷31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ज़10/- मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ज़57/- के लाभांश की सिफारिश की गई है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।÷ कंपनी द्वारा रिकॉर्ड तिथि की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

मार्च तिमाही के नतीजे

कंपनी ने 3,710 करोड़ रुपये का रेवेन्यू पोस्ट किया, जो QxFY25 में 3,935 करोड़ रुपये की तुलना में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। कर के बाद लाभ (पीएटी) भी 4.2 प्रतिशत बढ़कर 446.49 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछली तिमाही में 428 करोड़ रुपये था। EBIT 567 करोड़ रुपये रहा, जो 545 करोड़ रुपये से बेहतर रहा, हालांकि कोई प्रतिशत परिवर्तन नहीं दिखाया गया। EPS (प्रति शेयर आय) में वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 12.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 23.51 रुपये हो गया। मार्जिन 15.3 प्रतिशत पर स्थिर रहा, जो निरंतर परिचालन दक्षता को दर्शाता है।

29 अप्रैल को खुल रहा है यह आईपीओ, कंपनी ने 55 से 58 रुपये सेट किया प्राइस बैंड

शेयर बाजार में अनिश्चितताओं के बीच Arunaya Organics Limited IPO खुलने जा रहा है। कंपनी का आईपीओ 29 अप्रैल को खुलेगा। निवेशकों के पास आईपीओ पर दांव लगाने के लिए 2 अप्रैल तक का मौका रहेगा। आज शुक्रवार को एसएमई कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने बताया है कि 55 रुपये से 58 रुपये प्राइस बैंड है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 2000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। इस लॉट साइज की वजह से निवेशकों कम से कम 1,16,000 रुपये का दांव लगाना होगा।

क्या करती है कंपनी

Arunaya Organics Limited की स्थापन 2010 में हुई थी। कंपनी स्पेशिएलिटी डाई बनाती है। कंपनी टेक्सटाइल, पेंट्स,प्लास्टिक, माइनिंग और फूड प्रोसेसिंग के लिए हाई क्वालिटी केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है।

कंपनी के आईपीओ का साइज 33.99 करोड़ रुपये का है। कंपनी के आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर फार से दोनों शामिल है। कंपनी 52.60 लाख फ्रेश शेयर और 6 लाख शेयर ऑफर फार सेल के तहत जारी करेगी। बता दें, इस एसएमई कंपनी का आईपीओ एनएसई में लिस्ट होगा।

किसके लिए कितना हिस्सा आईपीओ में रहेगा?

Arunaya Organics Limited IPO में अधिकतम 20 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित है। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए 40 प्रतिशत और एनआईआई के लिए 40 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा।

टाटा की कंपनी का बढ़ गया 20 प्रतिशत मुनाफा, डिविडेंड देने का भी ऐलान

मार्च तिमाही में सालाना आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 प्रतिशत बढ़ गया। तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 189 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 157 करोड़ से अधिक है।

टाटा समूह की आईटी प्रोडक्ट एवं सर्विस प्रोवाइडर कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने शुक्रवार, 25 अप्रैल को मार्च तिमाही के नतीजे घोषित किए। मार्च तिमाही में सालाना आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 20प्रतिशत बढ़ गया। तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़189 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के ज़157 करोड़ से अधिक है। रेवेन्यू ज़1,286 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के ज़1,301 करोड़ से थोड़ा कम है।

क्या है डिटेल

टाटा टेक की ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले

की आय 233.5 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष मार्च तिमाही की तुलना में 2.7 प्रतिशत कम है। तिमाही के लिए ईबीआईटीडी मार्जिन पिछले वर्ष के 18.5प्रतिशत से घटकर 18.2प्रतिशत हो गया। तिमाही के लिए ईबीआईटीडीए मार्जिन पिछले साल के 18.5प्रतिशत से घटकर 18.2प्रतिशत हो गया।

डिविडेंड भी देगी कंपनी

टाटा टेक्नोलॉजीज ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 8.35 का अंतिम डिविडेंड और 3.35 का एकमुश्त विशेष डिविडेंड देने की सिफारिश की है, जो 2 के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए कुल मिलाकर ज़11.70 होगा। यदि सालाना आम बैठक में डिविडेंड को मंजूरी मिल जाती है, तो एजीएम के समापन से 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।

शेयरों के हाल

आय की घोषणा से पहले टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार को 3.51प्रतिशत गिरकर 692 पर आ गए थे। यह शेयर लिस्टिंग के दिन के अपने शिखर 1,400 से काफी नीचे है, लेकिन अपने आईपीओ प्राइस ज़500 से ऊपर बना हुआ है। टाटा टेक्नोलॉजीज दो दशकों में टाटा समूह का पहला आईपीओ था, जिसने पिछले साल के अंत में शेयर बाजार में अपनी शुरुआत की थी।

राष्ट्रबाण
सिवनी, शनिवार 26 अप्रैल 2025

बालाघाट राष्ट्रबाण

● बैहर ● बिरसा ● कटंगी ● तिरोड़ी ● कटंगी ● खैरलांजी ● किरनापुर ● लालबर्रा ● लांजी ● परसवाड़ा ● वारासिवनी

इतवारी बाजार मंडी पार्किंग जोन जुलाई तक बनकर होगा तैयार

रामपायली नदी तक सड़क, घाट, बगीचा और प्रतीक्षालय के कार्य हुए स्वीकृत

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में 19 विभागों द्वारा 139 कार्यो को दिया जा रहा मूर्त रूप

बालाघाट। राष्ट्रबाण

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में 19 विभागों द्वारा 139 कार्यों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। ये 139 कार्य न सिर्फ नगरों में विकास कार्य है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, सीसी रोड़, सामुदायिक भवन और स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण के भी कार्य है। शुक्रवार को कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने वर्ष 2022 से स्वीकृत कार्यों की वस्तु स्थिति जानने के लिए समीक्षा बैठक रखीं। डीएमएफ के तहत पीडब्ल्यूडी को 15 निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा पीएचई के 34, जल संसाधन विभाग के 3, आरईएस संभाग-1 के 5 व सम्भाग-2 के 10 स्वास्थ्य विभाग के 6 और सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को 79 स्वीकृत कार्य है। 8437 लाख रुपये की लागत से 139 स्वीकृत कार्यों में 127 प्रगतिरत है, जबकि 12 पूर्ण हो चुके है, जबकि अधिकांश कार्य 15 मई तक पूर्णता होने की जानकारी विभागों द्वारा दी गई है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री अडमे ने बताया कि इतवारी गंज मंडी में दो पार्किंग जोन का निर्माण कार्य चल रहा है। यह कार्य जुलाई तक पूर्ण होगा। यह 50-50 चार पहिया वाहनों की पार्किंग का कार्य चल रहा है। इसी तरह आमगांव- बरबसपुर,अंजुमन सामुदायिक भवन में स्लैब का कार्य,रैनबसेरा से आंगनवाड़ी तक सड़क व सिकंदरा में डॉ. अम्बेडकर सामुदायिक भवन का कार्य है। इसी तरह नगर पालिका द्वारा म्युनिसिपल स्कूल के सामने 12 लाख रुपये की लागत से सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने समीक्षा के दौरान 2022-23 के स्वीकृत कार्य हर हाल में 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए है। वहीं अगर कोई कार्य अप्रारम्भ है तो वे कार्य निरस्त किये जायें।

सर्राटी जलाशय अगस्त तक पूर्ण करने की हिदायत

कलेक्टर श्री मीना ने डीएमएफ मद से जल संसाधन विभाग को 3 कार्यो की स्वीकृति दी है। उनमे से सर्राती जलाशय के कार्य को अगस्त तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग को लालबर्रा, कटंगी, परसवाड़ा व खैरलांजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपकरण खरीदी के लिए 54 लाख रुपये स्वीकृत किये है। इसके अलावा मप्र टूरिस्म विभाग अंतर्गत रामपायली में नदी तक पहुँचने के लिए सड़क निर्माण, बगीचा और यात्री प्रतीक्षालय के कार्य भी स्वीकृत किये है।

टूरिज्म की ओर बढ़ते बालाघाट के कदम

हिल स्टेशन की तरह विकसित होंगे बालाघाट के 4 स्थल, मप्र टूरिज्म विभाग ने दी हरी झंडी

गांगुलपारा, लगमा, आरामटोला को हिल स्टेशन की भांति विकसित किया जाएगा, बैगा हाट को पुन : विकसित करने की नई योजना

बालाघाट। राष्ट्रबाण

वन्य जीवों, ताजी हवा और आकर्षित करती बालाघाट की हरियाली भरी भूमि के 4 स्थलों पर हिल स्टेशन की तरह विकसित करने के प्रयास प्रारम्भ हुए है। इसके लिए कलेक्टर मृणाल मीना ने अपने निर्देशन में स्थलों का चयन कर प्रस्ताव तैयार कराए। उनके द्वारा तैयार कराए गए प्रस्तावों में बैगा हाट बाजार को पुनः विकसित करने की मप्र टूरिज्म विभाग से अनुमति मिल चुकी है। तैयार किये प्रस्ताव के अनुसार शहर के करीब प्राकृतिक सौन्दर्यता बिखेरने वाले गांगुलपारा, राष्ट्रीय टायगर रिजर्व से सटे गांव लगमा और आरामटोला को चुना गया है। इन स्थलों को विकसित करने के प्रस्ताव भेजें गए है। साथ ही लगमा में ही स्थापित बैगा हाट बाजार को पुनः नए कलेवर के साथ विकसित करने की रूपरेखा तैयार की गई है।

हवा में साइकिलिंग,जंगल के रास्तों पर ट्रेकिंग, हवा में उड़ने जैसे एडवेंचर वाले खेलों से युक्त होंगे स्थल

जिला पुरातत्व पर्यटन व संस्कृति परिषद द्वारा बालाघाट के चुनिंदा स्थलों को हिल स्टेशन का रूप देने के प्रयासों में गांगुलपारा, लगमा व आरामटोला जलाशय, झरने व प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से निहारने सहित प्रकृति को करीब से महसूस करने के लिए कुछ एडवेंचर व मनोरंजक खेलों को अपनाया जाएगा। प्रस्ताव में गांगुलपारा में ज़िप लाइन, फॉक्स लाइन,एटीवी बाइक राइड, पेंट वॉल, रॉकेट इजेक्टर, स्काय साइकिलिंग, गो-कार्टिंग और हाइकिंग जैसे रोमांचक व मनोरंजक खेलों को शामिल किया गया है। यानी कोई व्यक्ति गांगुलपारा पहाड़ी से झरने व जंगल की खाइयों को पार करने का अनुभव करना चाहता है तो ज़िप लाइन से लटकते हुए कर सकेंगे। इसी तरह तारों पर पहाड़ी वाले स्थलों पर साइकिलिंग का भी अनोखा अहसास पर पाएंगे। साथ ही जंगल के ऊबड़खाबड़, रेतीले व पगडंडियों वाली सड़को पर बाइक राइड का आनंद ले सकेंगे। वहीं लगमा इन सब के साथ सायकिल ट्रेल जो जंगल के रास्तों से साइकिलिंग का सुखद अनुभव होगा।

जलाशय के करीब रहने वाले पक्षियों को निहारने का अवसर होगा

कान्हा टाइगर रिजर्व के पास ही आरामटोला में बर्ड वॉचिंग गतिविधि भी प्रारम्भ होगी। इसके साथ ही वॉच टॉवर व सायकिल ट्रेल प्रारम्भ की जाएगी। यहां जलाशय के इर्द गिर्द प्राकृतिक आवास में रहने वाले वन्य जीवों को देखने की व्यवस्थाएं की जाएगी। इसके अलावा बैगा हाट बाजार को पुन : व्यवस्थित करते हुए आकर्षक बाउंड्रीवाल व वेटिंग रूम बनाये जाएंगे। साथ ही ओपन थियेटर व अन्य कार्यो की मरम्मत भी की जाएगी।

डीएटीसीसी और उपसमिति करेगी संचालन

कलेक्टर श्री मीना ने निर्देशन में बनी योजना के तहत पूर्व के अनुभवों को देखते हुए। इन सब के व्यवस्थित रूप से संचालन के लिए जिला पुरातत्व पर्यटन संस्कृति परिषद के अलावा एक उपसमिति को कार्य सौंपा जाएगा। लगमा में पूर्व में बनी वन समिति भी संचालन के कार्य करेंगी।

1200 किलो महुआ लाहन के साथ 67 लीटर हाथ भट्टी शराब की जब्त

बालाघाट। राष्ट्रबाण

कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार उरांव के मार्गदर्शन मे मदिरा का अवैध विनिर्माण, संग्रहण एवं विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर की जा रहीं है। शुक्रवार को आबकारी वृत वारासिवनी एवं वृत कटंगी के द्वारा ग्राम सेल्वा, साल्हे और चिखला मे कार्यवाही की गई। जिसमें प्लास्टिक की पन्नियों एवं डिब्बो में भरा हुआ लगभग 1200 किलोग्राम महुआ लाहन के साथ 67 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त कर कुल 03 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जप्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 1,30,000 रूपये बताया गया है। इस कार्यवाही मे वृत प्रभारी संदीप श्रीवास, रमाकांत बघेल, मुख्य आरक्षक द्वारसिंह उइके, आरक्षक अतरलाल उइके, नरसिंह टेकाम, लखन चौधरी, भानुप्रताप, मेघना राय एवं अनिता कुमरे उपस्थित रहे।

बम्हनगाँव में प्याऊ का हुआ शुभारंभ

बालाघाट। राष्ट्रबाण

कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशन के जिले में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जल गंगा संवर्धन अभियान में जिले वासियों द्वारा अपना योगदान सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को नवांकुर संस्था राज भूषण सोशल सोसाइटी भूआ द्वारा अपने सेक्टर क्रमांक 01 के प्रश्नफुटन ग्राम बम्हनगाव में निशुल्क प्याऊ का शुभारंभ किया गया। जिससे कि राहगीरों को शुद्ध व शीतल जल पीने को मिल सकेगा।

नेशनल लोक अदालत 10 मई को

बालाघाट। राष्ट्रबाण

राष्ट्रीय एवं मप्र विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर जिला न्यायाधीश श्री प्राणेश कुमार प्राण के मॉगदर्शन में 10 मई 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये लोक अदालत जिले में जिला न्यायालय, श्रम न्यायालय, कुटुंब न्यायालय व समस्त न्यायालयों में आयोजित होगी। लोक अदालतों में न्यायालयों में लंबित आपराधिक, विद्युत, चेक डिसऑनर, दीवानी एवं शमनीय मामलों के अलावा बैंक, श्रम, दूरसंचार, राजस्व, जलकर, संपत्तिकर व अन्य प्री-लिटिगेशन मामले निराकरण के लिए रखे जाएंगे। नेशनल लोक अदालत के वृहद प्रचार प्रसार के लिए प्रधान जिला न्यायधीश श्री प्राण के द्वारा जिला न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया की इस लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के लंबित पुराने मामलो का निराकरण करने के साथ साथ जलकर व संपत्तिकर पर विभिन्न प्रकार की छूट दी जाएगी। जिसकी जानकारी प्रचार प्रसार वाहन के माध्यम से दी जाएगी। ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल,जिला न्यायाधीश गौतम सिंह मरकाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह, अविनाश छारी, तारा मार्को, सिखा शर्मा, शुभम जैन, सिनी जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे, चीफ लीगल एंड डिफेन्स कौंसिल श्री बसंत डहाके व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहें।

शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी

बालाघाट। जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट अंतर्गत संचालित विभागीय शैक्षणिक शालाओं में कार्यरत प्रधान पाठक, उच्च श्रेणी शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्यायाम अनुदेशक प्राथमिक शिक्षक एवं खेलकूद शिक्षक की 01 अप्रैल 2025 की स्थिति में अनन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर समस्त संकुल प्राचार्यों को उपलब्ध करा दी गई है। जनजातीय कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार संबंधित शिक्षक अपने संकुल प्राचार्य के कार्यालय में वरिष्ठता सूची का अवलोकन कर सकते है। वरिष्ठता सूची में कोई आपत्ति हो अथवा किसी शिक्षक का नाम छूट गया हो या कोई प्रविष्टि इन्द्राज न हो तो, वे शिक्षक लिखित में आपत्ति तथा आपत्ति का कारण एवं पुष्टि के लिए 15 दिवस के भीतर संपर्क करें।

लापरवाह सीएमओ पर गिरी गाज

जबलपुर कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से कटंगी सीएमओ को किया निलंबित

रुचि लेकर नहीं कर रहे थे दायित्वों का निर्वहन, कार्य प्रगति भी हो रहीं थी ठप्प

बालाघाट। राष्ट्रबाण

संभागीय कमिश्नर अभय वर्मा ने सीएमओ रवि प्रकाश श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित के आदेश जारी किए है। मामला कटंगी का है,जहाँ सीएमओ रवि प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा शासकीय योजनाओ के प्रगतिरत कार्यो में रुचि लेकर व तन्मयता के साथ कार्य करना नहीं पाया गया है। कई योजनाओं में प्रगति रुकने के कारण कलेक्टर मृणाल मीना ने जबलपुर सम्भागयुक्त अभय वर्मा को कार्यवाही के लिए प्रस्ताव भेजा था। भेजे गए प्रस्ताव में बताया गया था कि 5 नवम्बर 24 को आयुष्मान कार्ड की प्रगति के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी जिसमे कटंगी सीएमओ श्री श्रीवास्तव अनुपस्थित रहें। इसके अलावा 5 दिसम्बर 24 को नगरीय निकाय की समीक्षा बैठक में पाया गया कि सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग दिसंबर माह की शिकायत में मात्र 22 शिकायते प्राप्त हुई थी किंतु 5 नवम्बर 24 तक 63.68 प्रतिशत में थे। इसी तरह हर माह की शिकायतों में कटंगी निकाय की प्रगति अल्प ही रहीं हैं। साथ ही निकाय ग्रेडिंग अधिकांश सी एवं डी में होती जा रहीं है। वहीं सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में जनवरी माह की प्राप्त ग्रेडिंग में 35 शिकायतों में से 18 शिकायतें शेष पायी गई। साथ ही 50 दिवस में 10 शिकायतें लंबित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत भी सबसे अधिक शिकायत लंबित रहती है। साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने में भी 59.70 प्रतिशत ही प्रगति पर है। कलेक्टर श्री मृणाल मीना से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार सीएमओ श्रीवास्तव को समय समय पर शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया किंतु सीएमओ द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं पाया गया।

संभागीय कमिश्नर श्री वर्मा ने समस्त कारणों का अवलोकन करते हुए निर्धारित कटंगी सीएमओ श्री श्रीवास्तव द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में पाया। फलस्वरूप कटंगी सीएमओ श्री श्रीवास्तव को मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 86 एवं मप्र नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम-36 तथा मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

नगर पालिका ने नगर के वॉशिंग केंद्रों पर की ताबड़तोड़ कार्यवाही

जल संकट की स्थिति में जल के अपव्यय को रोकना अनिवार्य

10 से ज्यादा कनेक्शन काटे, 2 से वसूला जुर्माना

बालाघाट। राष्ट्रबाण

जिले में इन दिनों जल संकट की स्थिति बनी हुई है। ज्ञात हो कि कलेक्टर श्री मृणाल मीना द्वारा जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। वहीं इन दिनों वैनगंगा नदी के जलस्तर में भी लगातार गिरावट हो रही है। साथ ही ग्रीष्मकाल के दो महीने अभी शेष है। ऐसे में शहरवासियों को जल की बचत करने के लिये जागरूक किया जा रहा है।नगे पालिका द्वारा वॉशिंग केंद्रों को भी सूचित कर जल की बर्बादी रोकने की हिदायत दी गई थी। इसके बावजूद नगर के वॉशिंग केंद्रों द्वारा जल की बर्बादी करते पाया गया। सीएमओ श्री बीडी कतरोलिया के निर्देशो पर नगरपालिका बालाघाट की जलप्रदाय एवं राजस्व शाखा की टीम ने नगर में कार्यवाही करते हुए लगभग 10 से अधिक वॉशिंग सेंटरों के कनेक्शन को विच्छेद किये गए। जबकि 2 वॉशिंग सेंटर संचालकों से जुर्माना भी वसूला गया है।

इन पर हुई कार्यवाही:

सीएमओ श्री कतरोलिया के निर्देशों के परिपालन में शहर के मैकेनिक नगर में संचालित होने वाले वॉशिंग सेंटर, काली पुतली चौक हनुमान मंदिर के पास गली में संचालित होने वाले वॉशिंग सेंटरों के अतिरिक्त फुले भवन के पास कार्यवाही करते हुए नल कनेक्शन विच्छेद किया गया है। इस पूरी कार्यवाही में लगभग 10 से अधिक वॉशिंग सेंटर शामिल है। जबकि राजस्व विभाग की टीम ने पानी का अपव्यय किये जाने पर भटेरा मार्ग के अमित सर्विसिंग सेंटर, चर्च रोड के न्यू जनता ऑटो केयर पर चालानी कार्यवाही करते हुए 800-800 रूपये का जुर्माना वसूला है।

वॉशिंग केंद्रों को यह रखनी होगी सावधानी

सीएमओ बीडी कतरोलिया ने सख्त निर्देश दिये है कि शहर में कहीं भी जल की बर्बादी नहीं होनी चाहिये। विशेषकर टिल्लू पंप से पानी खिंचने वालों, आरओ वॉटर संचालन, वॉशिंग सेंटरों, खुले नलों से बहते पानी को रोकने, टंकियों में ओवरफ्लो पर निगरानी बरतने जैसे कार्यो पर गंभीरता से अमल करने को कहा गया है। सीएमओ ने बताया कि निरंतर यह कार्यवाही जारी रहेगी और जहां भी जल की बर्बादी के संबंध में शिकायत आएगी तो सख्त कार्यवाही की जायेगी।

जल नहीं जल स्त्रोत बचेंगे तो कंठ तर होंगे

बालाघाट। राष्ट्रबाण

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में लगातार जल संरक्षण व संवर्धन को लेकर गतिविधियां आयोजित हो रही है। एक अनोखी गतिविधि गुरुवार को दुर्गम पहाड़ी व वनीय गांव हर्राभाट में जन अभियान परिषद की नवांकुर समिति, जल जीवन ग्रामीण व प्रस्फुटन समिति द्वारा आयोजित की गई। हर्राभाट के मिट्टी के मकान में चौपाल पर ग्रामीणों को पानी की पाठशाला में बताया कि सिर्फ जल नहीं अब हमें जल स्त्रोत भी बचाने और बनाने होंगे। क्योंकि जल स्त्रोत बचेंगे तो हमारे लिए उपयोग के लिए जल होंगा। इसलिए जल जितना जरूरी है, उससे कहीं अधिक जल स्त्रोत आवश्यक हो गए है। आज

मिट्टी के मकान की चौपाल पर पानी की पाठशाला

चाहे बावड़िया हो या कुएं हो या नलकूप,नदियां, नाले,तालाब और रिचार्ज पीठ या हार्वेस्टिंग हो ये सब कल हमें जल देंगे। इसके साथ ही पौधे जल स्त्रोतों के साथ मिलकर पानी बचाकर रखेंगे। चौपाल के पश्चात गांव में स्थापित हेंडपम्प के आसपास साफ-सफाई करके श्रमदान किया गया। ग्रामीणों को बताया गया कि हैंडपम्प हम सभी के लिए प्राथमिक पेयजल की व्यवस्था है और इसके आसपास सदैव सफाई होना जरूरी है। इस चौपाल का आयोजन विकासखंड समन्वयक संतोष नगपुरे व सुशील बर्मन के निर्देश में किया गया। चौपाल के दौरान कई ग्रामीण उपस्थित थे।

राष्ट्रबाण
सिवनी, शनिवार 26 अप्रैल 2025

सिवनी-बैतूल राष्ट्रबाण

● बरघाट ● छपारा ● धनोरा ● घंसौर ● केवलारी ● कुरई ● लखनादौन ● सिवनी ग्रामीण ● मुलताई ● बैतूल बाजार ● आमला ● भैंसादंड ● सारणी ● बोरदई ● आठनेर

ठेंगे पर नियम : ग्राम नगझर में शराब दुकान के प्रचार बोर्ड, नियमों का उड़ा रहा मजाक।

ग्राम पंचायत नगझर में संचालित शराब दुकान

विज्ञापन नियमों का कर रही उल्लंघन

हाइवे में अवैध रूप से लगा शराब दुकान का बोर्ड, कार्यवाही बनी आबकारी विभाग के लिए चुनौती

सिवनी। राष्ट्रबाण

शराब दुकान के प्रचार पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध है लेकिन कुछ शराब ठेकेदार द्वारा शासन और सरकार के नियमों को जूते की नोंक पर रौंदा जा रहा है।

ग्राम पंचायत नगझर में हाइवे मार्ग पर लगा शराब दुकान के प्रचार का बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार के आबकारी विज्ञापन एवं प्रचार के नियमों को चुनौती दे रहा है। वैसे तो शराब और शराब दुकान के प्रचार पर शासन ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। लेकिन शासन के नियमों की ऐसी तैसी करते हुए शराब ठेकेदार द्वारा हाइवे में बिना किसी परमिशन के शराब दुकान का बोर्ड लगाया हुआ। हाइवे में लगा यह बोर्ड ग्राम पंचायत नगझर में लगा हुआ है। बुद्धिजीवियों का मानना है कि शराब दुकान का ऐसा प्रचार ठेकेदार नहीं कर सकते।

राष्ट्रबाण ने जब इस संबंध में आबकारी अधिकारी विनोद कुमार खटीक से शराब दुकान के प्रचार पर नियम पर ध्यान आकर्षित कराया गया तो उन्होंने उक्त शराब दुकान को शहरी क्षेत्र में बताया और नियमों के बाहर होने की बात कही। वहीं जानकारों का मानना है कि शराब दुकान का बोर्ड ग्राम पंचायत नगझर में लगा हुआ है और यह बोर्ड शराब दुकान से दूरी में लगा है। जबकि शराब ठेकेदार शराब दुकान के प्रचार का बोर्ड सिर्फ दुकान के सामने लगा सकते है, दुकान से दूर शराब दुकान के प्रचार का कोई प्रावधान नहीं है। आबकारी अधिनियम के अनुसार बिंदु क्रमांक 23 ए. (शराब से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिषेध। मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 23, 1978 द्वारा अंतःस्थापित) (1)

इस खंड में, ÷विज्ञापन÷ में कोई भी नोटिस, परिपत्र, लेबल, आवरण या अन्य दस्तावेज़ के रूप में शराब दुकान का प्रचार नहीं कर सकते यह स्पष्ट है लिखा हुआ है। लेकिन शराब ठेकेदार द्वारा खुलेआम नियमों का मखौल उड़ाया जा रहा है।

कार्यवाही करने की आबकारी विभाग की हिम्मत नहीं

शराब दुकान के प्रचार बोर्ड पर विवाद उत्पन होने के बाद अब एक नई चर्चा छिड़ गई है। लोगों का कहना है कि शराब ठेकेदारों से आबकारी विभाग मोटी रकम लेता है। हर महीने ठेकेदारों द्वारा इन्हें चढ़ौतरी चढ़ाई जाती है। ऐसे में इनसे कार्यवाही की उम्मीद बेइमानी है। ज्ञात हो कि विगत वर्ष तत्कालीन आबकारी अधिकारी द्वारा शराब ठेकेदार से 3.50 लाख रूपये महीने की वसूली को बढ़ाने को लेकर लोकायुक्त ने कार्यवाही की थी जिसके बाद यह खुलासा हुआ था कि शराब ठेकेदार से आबकारी विभाग में बैठे जिम्मेदारों द्वारा लाखों रूपये की घुस हर महीने ली जाती है जिसके चलते आबकारी विभाग शराब ठेकेदारों पर निगाहे करम बनाए रखते है। शायद नियमों को भूलने की एक वजह यह भी हो सकती है।

मनीष जाट, शराब ठेकेदार : नियमों को रौंद रहे जूते की नोंक पर!

नरसिंहपुर के ठेकेदार का दबदबा

नगझर में संचालित शराब दुकान का ठेकेदार मनीष जाट नरसिंहपुर से है। बताया जाता है कि मनीष जाट का राजनैतिक रसूख है और यह विभागीय अधिकारियों से भी पूरी तरह तालमेल बना कर रखता है। आबकारी विभाग में अफसरों से लेकर छोटे कर्मचारियों तक मनीष जाट का दबदबा है। शायद यही वजह है कि आबकारी अधिकारी भी ग्राम पंचायत नगझर में लगे बोर्ड को नगरी सीमा में बता रहे है।

तीन तलाक पीड़िता ने राखी भेजकर प्रधानमंत्री मोदी को कहा शुक्रिया

उर्दू में पत्र भेजकर तीन तलाक कानून के लिए जताया आभार

कहा- मोदी भाई नहीं होते तो इंसाफ न मिलता

बैतूल। राष्ट्रबाण

बैतूल की रहने वाली सबा अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उर्दू में एक पत्र और राखी भेजकर उनका आभार जताया है। सबा अली ने कहा कि मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए जो ट्रिपल तलाक कानून बनाया है, उसकी वजह से आज उन्हें न्याय मिल सका। अगर यह कानून नहीं होता, तो शायद उनकी बात कभी सुनी ही नहीं जाती।

सबा अली ने बताया कि उनके पति ने उन्हें सड़क पर सबके सामने ट्रिपल तलाक दे दिया था। जब वह इसकी शिकायत लेकर बैतूल पुलिस के पास पहुंचीं, तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। पुलिस केस दर्ज करने को तैयार नहीं थी। उस समय वह बेहद परेशान और हताश थीं। ऐसे में उन्होंने बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री जनाब नरेंद्र शिवाजी पटेल से मुलाकात की और अपनी आपबीती सुनाई।

सबा अली ने बताया कि प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने उन्हें ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। उन्होंने तत्काल बैतूल के एसपी और कलेक्टर को निर्देशित किया और इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके लिए उन्होंने मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का भी आभार जताया है।

सबा अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि देश की हर मुस्लिम बेटी को इंसाफ मिले और वह सुरक्षित रह सके। उन्होंने यह भी लिखा कि यह पत्र एक बहन की तरफ से एक भाई के लिए है और उसके साथ एक राखी भी भेजी है। पत्र के अंत में उन्होंने लिखा- दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है।

इस भावनात्मक अंदाज़ में राखी भेजकर सबा अली ने प्रधानमंत्री को मुस्लिम महिलाओं की तरफ से एक प्रतीकात्मक सम्मान दिया है और उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार आगे भी इसी तरह महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कड़े कदम उठाती रहेगी।

अवैध गर्भपात के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग

सबा अली ने प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से करुणा हॉस्पिटल की संचालक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। सबा अली का आरोप है कि ने उन्हें गर्भपात के लिए दवाइयां दीं, जिसके बाद उनका गर्भपात हो गया। उन्होंने इस मामले की शिकायत जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन और एसपी से की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब सबा अली ने राज्य मंत्री से गुहार लगाई है कि करुणा हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज जप्त कर जांच की जाए और दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

भाजपा सरकार को नहीं है किसानों और गरीबों की कोई चिंता : रमेश गायकवाड़

बैतूल। राष्ट्रबाण

किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को किसानों और गरीबों की कोई चिंता नहीं है। सरकार की प्राथमिकता अब शव वाहन खरीदने की हो गई है, जबकि अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं का बुरा हाल है।

रमेश गायकवाड़ ने कहा कि राज्य में मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है, और 60 वर्ष से कम आयु के लोग अधिक मर रहे हैं। इसके बावजूद भाजपा सरकार इलाज की व्यवस्था दुरुस्त करने की बजाय शव वाहन खरीदने जा रही है। यदि सरकार सभी शासकीय जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की पूरी नियुक्ति कर दे, तो बेरोजगारी घटेगी, इलाज मिलने से मौतों की संख्या में भी कमी आएगी।

उन्होंने कहा कि इलाज के दौरान गरीब और किसान आर्थिक संकट में आ जाते हैं। उन्हें सही समय पर सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पाता और उन्हें मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जहां खड़े होने तक की जगह नहीं मिलती। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी है, जिससे अस्पताल खाली पड़े हैं।

रमेश गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि सरकार इलाज की चिंता छोड़कर मौत की व्यवस्था में जुटी है। किसान अपने उत्पादों के वाजिब दाम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी जेबें खाली हैं लेकिन सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां खोखली हैं और अब प्रदेश की जनता इन्हें समझ चुकी है। किसान कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार इलाज और रोजगार की व्यवस्था करे।

बाल विवाह रोकथाम के लिए कर रहे लोगों को जागरुक

अक्षय तृतीया पर एक भी बाल विवाह न हो, 50 गांवों में चल रहा है जनजागृति कार्यक्रम

गंज कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में बालिकाओं के साथ किया संवाद

बैतूल। राष्ट्रबाण

प्रदीपन संस्था बैतूल द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत निर्माण के संकल्प के साथ जिले में 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जिले में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अक्षय तृतीया को दृष्टिगत रखते हुए यह अभियान खास तौर पर इस बात पर केंद्रित है कि जिले में एक भी बाल विवाह न हो। अभियान के अंतर्गत 50 गांवों में नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन, ग्राम सभाएं, रैलियां, स्कूल संवाद एवं जनसमुदाय के बीच बातचीत जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह की कुप्रथा पर प्रभावी रोकथाम करना, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी देना और बालिकाओं की सुरक्षा पर गहन संवाद स्थापित करना है।

अभियान के तीसरे दिन गंज स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बालिका सुरक्षा को लेकर एक संवाद सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 से अधिक बालिकाओं ने सहभागिता की। इस संवाद के दौरान बालिकाओं को दो प्रकार के ÷मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ जब...÷, ÷मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ जब...÷कार्ड प्रदान किए गए। इस दौरान बालिकाओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को विद्यालय की दीवारों पर चस्पा किया गया और उनके संदेशों का विश्लेषण किया गया। इसके अनुसार बालिकाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं जब वे घर पर अकेली होती हैं। स्कूल, बस, ट्रेन, या बाजार आते-जाते समय अकेली होती हैं। कोचिंग सेंटर, पार्क, या शराब की दुकानों के पास से गुजरती है। घर में कोई अनजान मेहमान आता है। दूर के रिश्तेदार या पड़ोसी पुरुष घर आते हैं। परिवार के सदस्य शराब या नशे की हालत में होते हैं।इसके विपरीत बालिकाओं ने स्वयं को माता-पिता, भाई, दादा-दादी, स्कूल के शिक्षकों और पुलिस थाने के साथ सुरक्षित महसूस करने की बात कही। अभियान के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा को निरंतर जारी रखें, अपने आत्म-सम्मान की रक्षा करें और किसी भी प्रकार की समस्या को संस्था से साझा करने में संकोच न करने के लिए प्रेरित किया गया।

संवेदनशील मुद्दों पर हुआ संवाद

संस्था की काउंसलर और बाल अधिकार कार्यकर्ता चारूलता वर्मा ने संवाद सत्र को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और मध्यप्रदेश क्राइम डेटा के माध्यम से यह बताया कि बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों के अधिकांश मामले उन्हीं लोगों द्वारा किए जाते है जो उनके निकट के रिश्तेदार होते है जैसे चाचा, मौसेरे भाई, मामा, दोस्त, अथवा पड़ोसी। चूंकि इन लोगों पर परिवारों द्वारा अधिक विश्वास किया जाता है, इस कारण लड़कियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। संस्था के कार्यकर्ताओं ने बालिकाओं को यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की असहज स्थिति में उन्हें बिना झिझक अपने माता-पिता, शिक्षक, या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आत्मरक्षा के सुझाव, पुलिस सहायता लेने की प्रक्रिया और आपातकालीन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए इन सभी बातों की विस्तृत जानकारी दी।

ग्रामीण क्षेत्र में निकाली जागरूकता रैली

प्रदीपन संस्था की टीम ने ग्राम लकड़जाम और भीमपुर क्षेत्र में जागरूकता रैलियों का आयोजन किया, जिसमें यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए दो साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना निर्धारित है। इस दौरान संस्था की टीम ने हजारों लोगों को पाम्फलेट बांटकर जागरूक किया। रैली और प्रचार कार्य में संस्था की कार्यकर्ता अल्का नागले, पूनम अतुलकर, ज्योति बाग्वे, विशाल आर्य, रवि चवारे और राकेश मन्ना ने रेखा गुजरे के मार्गदर्शन में गांव-गांव घूमकर लोगों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी।

वाहनों में पट्टा लगाकर हो रहा था अवैध परिवहन

बैतूल। राष्ट्रबाण

कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शुक्रवार को खनिज विभाग ने वाहनों में अतिरिक्त पट्टा लगाकर गौण खनिज का अवैध परिवहन कर रहे तीन डंपरों को जप्त किया है।

जिला खनिज अधिकारी मनीष पालेवार ने खनिज विभाग द्वारा शुक्रवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बैतूल तहसील के अंतर्गत खनिज रेत का वाहनों में अतिरिक्त पट्टा लगाकर अवैध परिवहन कर रहे डम्पर क्रमांक एमपी 48 जेडई 9832 एवं एमपी 48 एच 1215 को खनिज नियमों के तहत जप्त किया जाकर पुलिस थाना गंज बैतूल की अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। इसी प्रकार तहसील घोड़ाडोंगरी अंतर्गत खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन कर रहे वाहन डम्पर क्रमांक एमपी 48 एच 0279 को खनिज नियमों के तहत जप्त किया जाकर पुलिस चौकी घोड़ाडोंगरी की अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। उक्त वाहनों के वाहन चालकों, वाहन मालिकों के विरूद्ध मध्यप्रदेश अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण नियम 2022 के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत कर कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही निरंतर जारी है।

पहलगाव आंतकी घटना के विरोध में सर्व हिन्दू समाज संगठन का आक्रोश सड़कों पर दिखा

पहलगाम हमले के विरोध में हर ओर आक्रोश

सारनी। राष्ट्रबाण

सर्व हिंदू समाज संगठन द्वारा 24 अप्रैल दिन गुरुवार साम 7 बजे पाथाखेड़ा के बस स्टैंड पर शहीद सुनील पवार लांस नायक को श्रद्धांजलि देते हुए हिंदू संगठन के नेता धार्मिक एवं सामाजिक बंधु एवं पत्रकार बंधुओ ने भारत के स्वर्ग पहलगाम जम्मू में हुई कायराना हरकत के विरोध में मसाल जुलूस का आवाहन किया जिसमें हिंदू संगठन के प्रमुख नेता लल्लन यादव लक्ष्मीकांत पांडे अमित गुप्ता चेतन गुप्ता सम्मिलित हुए हिंदू संगठन के नेताओं ने बताया कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने अपनी कायरतापूर्ण हरकत को फिर से जाहिर किया है मासूम टूरिस्टओ के साथ धर्म पूछ कर गोली मारना एव निहत्तो पर गोली चलाना कायरता का प्रतीक है ऐसे जिहादियों के खिलाफ विरोध प्रदेशन में मशाल जुलुश निकाल नारेबाजी की गई जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता देवेन्द्र भादे,राकेश बारंगे,डब्बू पंवार, सुधा चंद्रा ,दीपक सिनोटिया,देवेंद्र सोनी, विज्जू वानखेड़े, राणा सिह, निशांत, विश्वजीत उपस्तिथि रही। साथ ही श्रमजीवी पत्रकार संघ बैतूल सारणी में निवासरत पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह, कालि चौरासे, संदीप झपाटे, योगेश बर्डे धर्मेंद्र राय, प्रकाश डहरिया, छविनाथ भारद्वाज, भीम बहादुर थापा , जुलूस में सम्मिलित हुए।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक संजय बघेल द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एमपी नगर भोपाल म.प्र से मुद्रित कराकर शिवनगर कॉलोनी सड़क मोहल्ला मरझोर जिला सिवनी से प्रकाशित।
RNI NO.: MPHIN/2015/72804 , **संपादक* संजय बघेल** पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र सिवनी होगा। E-mail: rashtrabaan@gmail.com. mob: 7000427433